लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार सरकार

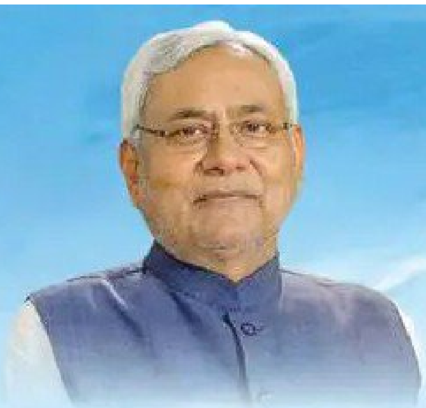

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को प्रतिबद्ध बिहार सरकार

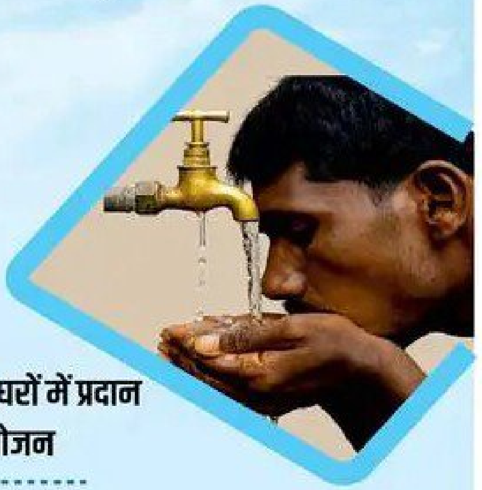

"हर घर नल का जल"

बिहार की पहल, देश के लिए मिसाल

- कुल **1,23,936** जलापूर्ति योजनाओं का किया गया निर्माण
- ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु **27,737** अतिरिक्त जलापूर्ति योजना निर्माणाधीन
- **11** जिलों में **14** बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण से फ्लोराइड व आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया शुद्ध पेयजल
- जल गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु **01** राज्य स्तरीय, **38** जिला स्तरीय एवं **75** अवर प्रमंडल स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला कार्यरत
- जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण, मरम्मति एवं संपोषण हेतु **संचालन एवं रख-रखाव नीति** लागू
- कुल **1,75,26,317** घरों में प्रदान किया गया गृह जल संयोजन
- **29,954** भूजल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों के **47.30** लाख घरों को आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन मुक्त 'नल का जल' उपलब्ध
- ग्रामीणों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन **70** लीटर पेयजल कराया जा रहा उपलब्ध
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित **70,544** विद्यालयों और **95,751** आंगनबाड़ी केन्द्रों में 'नल का जल' उपलब्ध
- पेयजल से संबंधी जन शिकायतों के निवारण हेतु **केन्द्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग** स्थापित

PR No.- 011266 (PHED)D. 2025-26

जलापूर्ति संबंधित शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर **(1800-123-1121/1800-345-1121/155367)**, व्हाट्सएप नंबर **(8544429024/8544429082)** या **'स्वच्छ नीर'** मोबाइल ऐप का उपयोग करें।

स्वच्छ नीर ऐप डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन करें:

सीएम की घोषणा • उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज

बिहार: ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन मिलेगी

विशेष पैकेज, सस्ता फॉर्म, नई भर्तियां

पॉलिटिकल रिपोर्टर। | पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज (विशेष आर्थिक पैकेज)' की घोषणा की। शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। सीएम ने बताया कि 'सात निश्चय-2' के तहत 2020 में 50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। अब सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। इसके लिए उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पैकेज लागू किया जा रहा है। ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीनों के भीतर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अलावा, राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों की महत्वपूर्ण सहायता के लिए कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

क्या होगा विशेष आर्थिक पैकेज में

1. कैपिटल-ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि दोगुनी होगी।

2. सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

3. ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन मिलेगी।

4. औद्योगिक भूमि से जुड़े विवादों का समाधान किया जाएगा।

भास्कर नॉलेज

बिहार का औद्योगिक विकास तेज होगा

प्रश्न. विशेष आर्थिक पैकेज क्यों?
▪ बिहार में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना।

प्रश्न. पैकेज में क्या सुविधाएं मिलेंगी?
▪ निवेश करने वाले उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी प्रोत्साहन राशि और मुफ्त भूमि दी जाएगी।

प्रश्न. ये सुविधाएं कब से लागू होंगी?
▪ यह सुविधाएं अगले 6 महीनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी। कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।

प्रश्न. क्या यह नए उद्योगों के लिए है?
▪ हां, यह नए निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे बिहार में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करें।

प्रश्न. जमीन की व्यवस्था कैसे होगी? ▪ सभी जिलों में औद्योगिक भूमि की व्यवस्था की जाएगी। जो ज्यादा रोजगार देंगे, उन्हें मुफ्त जमीन मिलेगी।

सीएम की 15 अगस्त की घोषणा... पीटी का फॉर्म 100 रुपए में, मुख्य परीक्षा फ्री

1. राज्य में होने वाली सभी आयोगों की पीटी परीक्षाओं का फॉर्म मात्र 100 रुपये में भरा जाएगा। मुख्य परीक्षा पूरी तरह निशुल्क होगी।
2. किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खुलेंगे।
3. त्योहारी सीजन (छठ, दिवाली, होली) में दिल्ली व अन्य शहरों से बिहार आने के लिए अतिरिक्त बसें व विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

शिक्षक भर्ती : टीआरई-4 में 1 लाख पद भरे जाएंगे

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 के जरिए 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें टीआरई 3 के 20,397 रिक्त पद भी जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा में होगी। राज्य के 28 हजार स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की योजना है, हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। 11 हजार पद विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए होंगे। एससी-एसटी विभाग के स्कूलों में 2 हजार से अधिक शिक्षक मिलेंगे। सामान्य विषयों में करीब 20 हजार शिक्षक नियुक्त होंगे।

कूटनीतिक रिश्तों में गर्माहट, पर कारोबारी संबंधों पर चीन की चुप्पी

उर्वरक आपूर्ति में नरमी का दिया संकेत, मगर रेअर अर्थ मैग्नेट पर अड़ा

विदेश मंत्री जयशंकर की आज चीनी समकक्ष वांग यी से होगी मुलाकात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीन की तरफ से भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को सुधारने को लेकर सहयोग के हर संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन यह बात आर्थिक संबंधों के बारे में नहीं कही जा सकती। खास तौर पर रेअर अर्थ मैग्नेट एवं कुछ दूसरे दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को खोलने को लेकर चीन सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया है। इस बारे में चीन की सरकार ने न तो भारतीय आटोमोबाइल कंपनियों की मांग पर कोई ध्यान दिया है और न ही भारत सरकार की तरफ से किए गए आग्रहों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

ऐसे में सोमवार शाम को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी की द्विपक्षीय मुलाकात पर उद्योग जगत की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया

वांग यी। फाइल

एस. जयशंकर। फाइल

गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी चीन यात्रा के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कारोबारी संबंधों से जुड़े होंगे।

सूत्रों ने बताया कि रेअर अर्थ मैग्नेट को लेकर चीन इस बात पर अड़ा है कि वह सिर्फ उन देशों की कंपनियों को इसकी आपूर्ति करेगा जिन्होंने इसके इस्तेमाल को लेकर समझौता किया है। यह समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि चीन जो दुर्लभ धातु निर्यात करेगा, उसका सैन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि चीन ने अप्रैल, 2025 में यह कहते हुए रेअर अर्थ मैग्नेट निर्यात को प्रतिबंधित किया था कि इसके रक्षा क्षेत्र में गलत इस्तेमाल की संभावना है। इस धातु का इस्तेमाल आटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है।

इसका असर भारतीय आटोमोबाइल कंपनियों पर बहुत ज्यादा पड़ा है। कुछ कंपनियों ने जापान एवं दूसरे देशों से इसकी आपूर्ति शुरू की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भारतीय कंपनियों के इस पक्ष को बीजिंग में भारतीय राजदूत ने भी उठाया था। लेकिन, अभी तक चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अब देखना होगा कि ताजा बातचीत के बाद चीन के रुख में कोई बदलाव आता है या नहीं।

दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कल पीएम मोदी से मिलेंगे वांग यी

चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मंगलवार को होने वाली उनकी यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है। मोदी की राष्ट्रपति शी चिनफिंग से द्विपक्षीय मुलाकात भी तय है। वांग की यात्रा को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। वांग यी जब पिछली बार द्विपक्षीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे, तब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी। इस लिहाज से चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए पीएम का समय देना इस बात की तरफ संकेत है कि भारत एवं चीन के रिश्तों में तनाव को खत्म करने की कोशिश तेज की गई है।

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

रोजगार के मामले में बदलता दृष्टिकोण

हाल की कुछ घटनाएं दर्शाती हैं कि कारपोरेट दुनिया के एक विशेष वर्ग ने शेयरधारकों के लिए अधिकतम मूल्य की खोज में कर्मचारियों की संख्या में कटौती किए जाने के रूप में एक नए और अजीब पैमाने की तलाश की है। सिलिकान वैली के दिग्गजों से लेकर भारत की आइटी कंपनियों तक, छंटनी की घोषणाएं गर्व के साथ की जाती हैं और शेयर बाजार एक तयशुदा उत्साह के साथ जोश में आकर उछाल दिखाता है। ऐसे में रोजगार के दृष्टिकोण से इस परिदृश्य को देखा जाना चाहिए, खासकर भारत के संदर्भ में इसके व्यापक निहितार्थों को भी समझा जाना चाहिए

प्रतीकात्मक

बीते दिनों कारपोरेट दुनिया की कुछ कंपनियों ने अपनी कार्यदक्षता को बढ़ाने और लाभप्रदता को अधिक करने के लिए कर्मचारियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। यह कभी अंतिम और गंभीर कदम माना जाता था, अब रणनीतिक दूरदर्शिता का तमगा बन गया है। मगर इस तात्कालिक वित्तीय उछाल की चमक के पीछे, एक जटिल और चिंताजनक कहानी उभर रही है। क्या यह कटौती का जुनून वाकई लंबे समय तक चल सकता है, या हम एक गहरे, नापसंद इंसानी और सांस्कृतिक नुकसान को जमा होते देख रहे हैं?

वस्तुतः आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी बदलावों के दौर में लागत कम करना तुरंत और ठोस लाभ देता है। निवेशकों के दबाव में जूझ रहे निदेशक, कम वेतन और मोटे मुनाफे के बीच सीधा रिश्ता देखकर राहत महसूस करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जो कम से कम मानव प्रयास के साथ अभूतपूर्व परिणाम देने का वादा करती है, एकदम सही बहाना बनती है। यह छंटनी को संकट का संकेत नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता का सबूत बनाती है। बाजार हमेशा अल्पकालिक नजरिया रखता है, इस कदम को उत्साह के साथ पुरस्कृत करता है, एक तात्कालिक कटौती को दीर्घकालिक रणनीति समझने की भूल करता है। लेकिन यह आसान गणित उस जटिल मानवीय पूंजी को नजरअंदाज करता है, जो वास्तविक और स्थायी मूल्य का आधार है।

भारत का मानवीय समीकरण : इस प्रवृत्ति की बारीकियां भारत में कहीं अधिक स्पष्ट हैं। हाल ही में बेंगलुरु से वाल स्ट्रीट जर्नल की एक काल्पनिक खबर ने बताया कि वैश्विक तकनीकी छंटनी का असर भारत जैसे समाज में कई गुना बढ़ जाता है, जहां नौकरी केवल वेतन से कहीं अधिक मायने रखती है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां नौकरी बदलना आम है, भारत में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि पूरे परिवार की भलाई का प्रतीक है। यह भाई-बहनों की शिक्षा, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को आधार देती है। जब कोई कंपनी अपने कार्यबल को "सही आकार" देने की बात करती है, तो वह अनजाने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुबंध तोड़ रही होती है। इसका सांस्कृतिक नुकसान भारी है: सामाजिक सम्मान की हानि, संस्थाओं में भरोसे का टूटना और एक व्यापक असुरक्षा की भावना, जो उपभोग और नवाचार को दबा देती है। हालांकि भारत के पारिवारिक दायित्व इस प्रभाव को बढ़ाते हैं, वहीं पश्चिमी देशों में भी नौकरी की असुरक्षा से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और उपभोक्ता खर्च में कमी देखी जाती है। एक विदेशी अखबार ने रेखांकित किया कि जहां पश्चिमी कंपनियां छंटनी को एक लेन-देन की घटना मानती हैं, भारत में इसे विश्वासघात के रूप में देखा जाता है, जो भविष्य की आकांक्षाओं के ताने-बाने को तोड़ देता है।

भारत का आइटी क्षेत्र, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास का आधार और लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है, इस "कटौती के जुनून" से खास तौर पर प्रभावित हुआ है। वर्ष 2023 में 50 लाख से अधिक पेशेवरों वाले इस क्षेत्र में छोटी-सी प्रतिशत कटौती भी लाखों लोगों की बेरोजगारी में बदल सकती है। खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों से आए उन लोगों के लिए जो तकनीकी केंद्रों में आए, ये नौकरियां सामाजिक उन्नति का रास्ता थीं, जो पूरे परिवार को बेहतर जीवन देती थीं।

"वैश्विक आर्थिक चुनौतियों" या "पुनर्गठन" के नाम पर हाल की छंटनी ने इस समूह को गहरी चोट पहुंचाई है। विचारणीय यह भी है कि पश्चिमी देशों की तरह मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव में, नौकरी छिनने का असर हमारे देश में गंभीर होता है, जो परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल देता है। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारों का कम खर्च छोटे व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करता है।

भरोसे का क्षरण : यह भरोसे का क्षरण सीधे कारपोरेट संस्कृति के केंद्र को प्रभावित करता है। वफादारी, जो कभी लंबी नौकरी का आधार थी, अब पुरानी बात लगती है। जब कर्मचारी अपने साथियों, खासकर लंबे समय तक सेवा देने वालों को दक्षता के नाम पर अचानक बर्खास्त होते देखते हैं, तो एक डर फैल जाता है। बचे हुए कर्मचारी, जिन्हें "बचने वाले" कहा जाता है, अक्सर बढ़े हुए काम के बोझ, थकान और इस चिंता से जूझते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। उनकी प्रतिबद्धता कम होती है, अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा घटती है, और उनका ध्यान नवाचार से हटकर केवल जीवित रहने पर केंद्रित हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण, संस्थागत स्मृति, मौन ज्ञान और वर्षों में बने मूल्यवान नेटवर्क हर निकलने वाले कर्मचारी के साथ बाहर चले जाते हैं। इस बौद्धिक पूंजी को फिर से बनाना, जो अक्सर महंगी और समय लेने वाली भर्ती प्रक्रियाओं से होता है, छंटनी के शुरुआती लागत-लाभ विश्लेषण में शायद ही शामिल होता है।

इसके अलावा, कम कर्मचारियों और निरंतर लाभप्रदता के बीच माना गया संबंध अक्सर एक भ्रामक द्वंद्व है। हालांकि तात्कालिक लागत बचत स्पष्ट है, नवाचार, रचनात्मकता और ग्राहक अनुभव पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। लगातार तनाव में काम करने वाला कार्यबल प्रयोग करने, जोखिम उठाने या वह अतिरिक्त प्रयास करने की संभावना कम रखता है, जो बाजार में अग्रणी कंपनियों को अलग करता है। ग्राहक सेवा, जो अक्सर गहरी लागत कटौती का पहला शिकार होती है, प्रभावित होती है, जिससे ब्रांड की छवि खराब होती है और राजस्व कम होता है। सच्ची लाभप्रदता, एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में केवल लागत कम करने का परिणाम नहीं, बल्कि मूल्य को अधिकतम करने की प्रक्रिया है, जो एक सशक्त कार्यबल से जुड़ी होती है। कंपनियां इस बात पर प्रतिस्पर्धा करती हैं कि कौन अधिक कटौती कर सकता है, न कि कौन सबसे अधिक मूल्य सृजित कर सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण : औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों के आगमन ने अक्सर कुशल हस्तशिल्प श्रमिकों को विस्थापित किया, जिससे व्यापक सामाजिक अशांति और शुरुआती श्रमिक आंदोलनों का जन्म हुआ। 20वीं सदी के मध्य में विनिर्माण में स्वचालन ने उत्पादकता बढ़ाई, लेकिन आटोमोटिव और इस्पात जैसे उद्योगों में नौकरी छिनने की चिंता भी पैदा की। 1980 के बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ इस तरह शुरू हुई जिसका लक्ष्य शेयरधारक मूल्य बढ़ाना था। इस दौर ने इस विचार को मजबूत किया कि कंपनियों की पहली जिम्मेदारी शेयरधारकों के प्रति है, कर्मचारियों के प्रति नहीं। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या कम करने की ओर जोर दिया गया, जिससे संस्थाओं में अविश्वास बढ़ा। परंतु यह समझना होगा कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच "सामाजिक अनुबंध" का क्षरण, जहां वफादारी का बदला नौकरी की सुरक्षा से मिलता था, एक दीर्घकालिक सामाजिक परिणाम रहा है। इससे काम के प्रति एक अधिक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है, जहां व्यक्ति अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं और अपने नियोक्ताओं की दीर्घकालिक सफलता में कम निवेश करते हैं, जिससे काम और समाज का ताना-बाना मौलिक रूप से बदल गया है।

दीर्घकालिक रणनीति को दी जाए प्राथमिकता

कारपोरेट द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए, इस बारे में भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कंपनियां कभी भी जानबूझकर इस तरह के उपाय या कदम नहीं उठाती हैं। फिर से कुछ हद तक यह आर्थिक चुनौतियों का चक्रीय जवाब है, मंदी के दौरान कारपोरेट की एक जानी-पहचानी प्रतिक्रिया। मंदी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या उपभोक्ता मांग में बदलाव जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के कारण छंटनी कभी-कभी अपरिहार्य होती है, कंपनियां अल्पकालिक जीवित रहने को प्राथमिकता देती हैं। फिर भी, मौजूदा दौर अलग लगता है, जिसमें एआइ की तकनीकी अनिवार्यता शामिल है। यह मानव श्रम के मूल्यांकन में एक बुनियादी बदलाव का संकेत देता है। निवेशकों का दबाव, जो शेयरों में तात्कालिक उछाल से बढ़ता है, इस व्यवहार को और मजबूत करता है। लेकिन इस बारे में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अंतिम हिसाब में कर्मचारी संख्या में कटौती का मौजूदा कारपोरेट जुनून, जो शेयरधारकों को तात्कालिक संतोष देता है, टिकाऊ विकास की नींव को कमजोर करने का जोखिम उठाता है। वर्ष 2023 के गैलप अध्ययन में पाया गया कि बार-बार छंटनी करने वाली कंपनियों में कर्मचारी जुड़ाव में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कम उत्पादकता और नवाचार से जुड़ा था। उत्साहित "दक्षता" अक्सर गहरे सांस्कृतिक नुकसान की कीमत पर आती है, जो वफादारी को कम करती है, नवाचार को दबाती है और एक व्यापक असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जो त्रैमासिक आय रिपोर्ट से कहीं आगे तक गूंजती है। एक कुशल उद्यम का असली मापदंड केवल लागत कम करने की उसकी क्षमता नहीं, बल्कि स्थायी मूल्य उत्पन्न करने की उसकी योग्यता है, जो मानव पूंजी के पोषण और सशक्तीकरण से जुड़ा है।

जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था एक जटिल भविष्य की ओर बढ़ रही है, कारपोरेट नेताओं को तात्कालिक स्प्रेडशीट से परे देखना होगा और यह पहचानना होगा कि डिस्पोजेबल श्रम पर आधारित समाज अंततः नाजुक है, जो किसी भी अल्पकालिक लाभ से कहीं भारी कीमत चुकाने के लिए बाध्य है। सवाल यह नहीं कि कोई कंपनी कितनी कमजोर हो सकती है, बल्कि यह कि मानव तत्व को व्यवस्थित रूप से कम करके वह कितनी मजबूत रह सकती है। (डा. विकास सिंह)

पहले पखवाड़े में एफपीआइ ने 21 हजार करोड़ निकाले

भारत-अमेरिका में व्यापारिक तनाव, कारपोरेट के कमजोर नतीजों का दिखा असर

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव, पहली तिमाही में कारपोरेट के कमजोर नतीजे और रुपये में कमजोरी के कारण अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने जमकर निकासी की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, 1-15 अगस्त के बीच एफपीआइ भारतीय शेयरों से 20,975 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। इसके साथ कैलेंडर वर्ष 2025 में एफपीआइ की शेयरों से कुल निकासी 1.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

एंजल वन के वरिष्ठ विश्लेषक वकार जावेद खान का कहना है कि आने वाले समय में टैरिफ से जुड़ी कार्यवाहियां एफपीआइ की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका और रूस के बीच तनाव में हालिया कमी और नए प्रतिबंधों की अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि भारत पर प्रस्तावित 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त के बाद लागू होने की संभावना नहीं है। यह बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने 18 वर्ष बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी(-) से अपग्रेड करके बीबीबी किया है। यह एफपीआइ के मनोबल को और बढ़ा सकता है। इससे पहले जुलाई में एफपीआइ ने शेयरों से 17,741 करोड़ रुपये की निकासी की थी। इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान तीन महीनों में एफपीआइ ने शेयरों में 38,673 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि एफपीआइ की सतत निकासी मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता के कारण हो रही है। बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका समेत तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों को लेकर अस्पष्टता ने जोखिम आधारित भावना को बढ़ावा दिया है।

1.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंची एफपीआइ की शेयरों से 2025 में कुल निकासी

4,469 करोड़ का निवेश किया सामान्य सीमा वाले डेट में इस महीने में

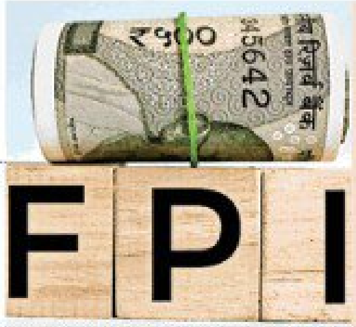

"हाल ही में अमेरिकी डालर की मजबूती ने भारत जैसे उभरते बाजारों के आकर्षण को कम किया है। इसके अलावा, सुस्त लाभ वृद्धि और ऊंची वैल्यूएशन ने भी निकासी में योगदान दिया है।

वीके विजयकुमार, मुख्य निवेश रणनीतिकार, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

डेट बाजारों में सकारात्मक निवेश

शेयरों से इतर, डेट या बांड बाजारों में पहले पखवाड़े के दौरान एफपीआइ का निवेश सकारात्मक रहा है। डिपाजिटरी के डाटा के अनुसार, 1-15 अगस्त के दौरान एफपीआइ सामान्य सीमा वाले डेट में 4,469 करोड़ रुपये, स्वैच्छिक रिटेंशन रूट वाले डेट में 232 करोड़ रुपये और फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) वाले डेट में 3,127 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। सरकारी बांड या सावरेन ग्रीन बांड एफएआर डेट के दायरे में आते हैं। इस श्रेणी के डेट में पूरे कैलेंडर वर्ष में एफपीआइ निवेश 37,787 करोड़ रुपये हो गया है।

पांच कंपनियों का पूंजीकरण 60 हजार करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीते सप्ताह शेयर बाजारों में तेजी की बदौलत बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 60,675.94 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान एसबीआइ के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 20,445.82 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के पूंजीकरण में 14,083.51 करोड़, इन्फोसिस में 9,887.17 करोड़, भारती एयरटेल में 8,410.6 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूंजीकरण में 7,848.84 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, एलआइसी, बजाज फाइनेंस, आइसीआइसीआइ बैंक, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड के पूंजीकरण में गिरावट रही है। बीते सप्ताह बीएसई सेंसेक्स में 739.87 अंक की वृद्धि रही थी।

पिछले वर्ष सेबी ने 284 याचिकाओं का निपटान किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पास निपटान याचिकाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सेबी ने वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में बताया कि पिछले वित्त वर्ष को उसे प्रतिभूति मानदंडों के उल्लंघन से जुड़े कुल 703 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 284 याचिकाओं का निपटान किया गया। यह दर्शाता है कि लंबी मुकदमेबाजी से गुजरे बिना विवादों को सुलझाने की प्रवृति बढ़ रही है। बीते वित्त वर्ष के दौरान 703 में से 272 आवेदन वापस ले लिए गए या अस्वीकार किए गए। निपटाए गए 272 आवेदनों से सेबी को 798.87 करोड़ रुपये मिले हैं। 2023-24 के दौरान सेबी को 434 निपटान आवेदन मिले थे।

अलास्का बैठक के बाद ट्रंप भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को लेकर पड़े नरम

शिखर वार्ता के बाद ट्रंप बोले–भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी

न्यूयार्क, प्रेट्र : अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को लेकर नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि हो सकता है कि अमेरिका उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएगा, जो रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि यदि अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा–खैर, उन्होंने (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने) एक तेल ग्राहक खो दिया, जो भारत है। वह लगभग 40% तेल का आयात कर रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अधिक आयात कर रहा है। अगर मैंने दूसरे चरण का प्रतिबंध या टैरिफ लगाया तो यह उसके लिए बहुत विनाशकारी होगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा। शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े। ट्रंप ने पुतिन के साथ शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय एयर फोर्स वन विमान में एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने बुधवार को कहा था कि यदि शिखर बैठक में ट्रंप और पुतिन के बीच चीजें ठीक नहीं रहीं तो रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त प्रतिबंध लग सकता है। ब्लूमबर्ग को दिए साक्षात्कार में बेसेंट ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन से हर कोई निराश है। हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अगर चीजें ठीक नहीं रहीं तो प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकता है।

ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की। इसमें रूस से तेल की खरीद जारी रखने पर जुर्माने के तौर पर लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। (पेज-11 भी देखें)

- अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा था–पुतिन से बात नहीं बनी तो भारत पर लगेगा अतिरिक्त टैरिफ
- बैठक से पहले ट्रंप ने कहा, रूस ने एक तेल खरीदार को खो दिया है और वह भारत है

पुतिन–ट्रंप शिखर सम्मेलन में प्रगति का भारत ने स्वागत किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर वार्ता का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का अंत जल्द देखना चाहती है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर बैठक का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का के एंकरेज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान। प्रेट्र

कपड़ा–फुटवियर से लेकर घी–मक्खन तक हो जाएंगे सस्ते

जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव से खानपान समेत दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में आएगी कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी प्रणाली से 12 और 28 प्रतिशत कर वाले स्लैब को समाप्त करने पर कपड़ा-फुटवियर से लेकर घी-मक्खन तक सस्ते हो जाएंगे। 1000 रुपये से अधिक कीमत वाले शर्ट-पैंट और फुटवियर खरीदने पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि 1000 रुपये से कम कीमत वाले शर्ट-पैंट व फुटविपर पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। अब सभी शर्ट-पैंट और फुटवियर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा।

सरकार की ओर से जारी नए प्रस्ताव के मुताबिक, 12 प्रतिशत के स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत उत्पादों को पांच प्रतिशत कर की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे में दैनिक रूप में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों उत्पादों पर अब पहले के मुकाबले सात प्रतिशत तक कम टैक्स लगेगा और ग्राहकों को कम कीमत चुकानी होगी। इनमें मुख्य रूप से ड्राइ फ्रूट, सभी प्रकार के पैक्ड नमकीन, प्रोसेस्ड फूड, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड नारियल पानी, पैक्ड जूस, 20 लीटर वाली पानी की पैक्ड बोतल, पास्ता, पेंसिल, टूथ पाउडर, जूट व काटन का हैंडबैग, शापिंग बैग, मोमबत्ती, टायलेट में इस्तेमाल होने वाले सामान, मच्छरदानी, म्यूनीज, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक व अन्य दवाइयां, पास्ता, परदा, किचनवेयर, फसल काटने वाली मशीन, थ्रेशिंग मशीन, मेडिसिनल ग्रेड आक्सीजन, सिंथेटिक धागे, एल्युमीनियम के बर्तन, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, नट-बोल्ट, सिलिकान वेफर, रेलवे में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद आदि शामिल हैं।

जीएसटी विशेषज्ञों का कहना है कि करों की दरों में बदलाव से सरकार के राजस्व पर इसलिए अधिक फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीएसटी के मद में मिलने वाला 65 प्रतिशत राजस्व 18 प्रतिशत के स्लैब से प्राप्त होता है। 12 प्रतिशत के स्लैब को हटाया जा रहा है और राजस्व संग्रह में इस स्लैब की हिस्सेदारी सिर्फ पांच प्रतिशत है। 12 प्रतिशत की जगह इन उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन उत्पादों को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। जीएसटी राजस्व में 28 प्रतिशत के स्लैब की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है और इसके उत्पादों को 18 प्रतिशत में शामिल कर दिया जाएगा। 28 प्रतिशत में काफी कम उत्पाद शामिल है। इसमें कई पर 40 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है।

- दरों में बदलाव से राजस्व में मासिक चार हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान
- विशेषज्ञों ने कहा, खपत बढ़ने से राजस्व में इस नुकसान की हो सकती है भरपाई

कपड़ों पर अभी मूल्य के लिहाज से पांच व 12% कर लगता है ● प्रतीकात्मक

पिछले वर्ष 1.8 लाख करोड़ रहा औसत संग्रह

वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी का मासिक औसत संग्रह 1.8 लाख करोड़ रहा है। जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत स्लैब की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत है और इस हिसाब 1.8 लाख करोड़ में उनकी हिस्सेदारी नौ हजार करोड़ रुपये होती है। डेलाइट के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) हरप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार के नए प्रस्ताव को देखते हुए राजस्व नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है और मोटे तौर पर यह नुकसान मासिक रूप से चार हजार करोड़ रुपये का दिख रहा है। 28 प्रतिशत में शामिल कई उत्पादों को सरकार 40 प्रतिशत में डाल सकती है। अभी इस दिशा में विचार चल रहा है। सिंह ने बताया कि रोजमर्रा के उत्पादों के सस्ता होने से कुछ समय बाद इनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे जीएसटी संग्रह में होने वाली क्षति की पूर्ति हो जाएगी।

जीएसटी में प्रस्तावित सुधार एकल कर स्लैब की दिशा में पहला कदम

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रस्तावित जीएसटी सुधारों को 'अगली पीढ़ी के जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि दो स्लैब वाली कर प्रणाली अंतत: एकल बिक्री-सेवा कर दर का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके 2047 तक लागू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली दरों में कमी के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और टैरिफ खतरों को कम करने में भी मदद करेगी। साथ ही कर दरों में उतार-चढ़ाव समाप्त हो जाएगा और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

भाजपा संसदीय बोर्ड में फैसला • ओबीसी समुदाय से हैं सीपी राधाकृष्णन, समर्थक इन्हें 'तमिलनाडु का मोदी' कहते हैं; चुनाव 9 सितंबर को

महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

भाजपा संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा के बाद उनका नाम तय हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगा। नड्डा ने कहा, 40 साल के करिअर में राधाकृष्णन हमेशा सियासी मुद्दों पर सार्वजनिक बयान से बचते रहे हैं।

- जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।
- नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो नौ सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन परिणाम आएगा।
- इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य वोट डालते हैं।
- संसद में 782 सदस्य हैं। एनडीए 427, इंडिया के 355 सांसद। बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। ऐसे में राधाकृष्णन का चुना जाना तय है।
- 2022 में धनखड़ को 528 वोट, विपक्षी प्रत्याशी मारग्रेट अल्वा को 183 वोट मिले थे। तब तृणमूल वोटिंग में शामिल नहीं थी।

इंडिया की बैठक आजः विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं।

16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े, दो बार सांसद

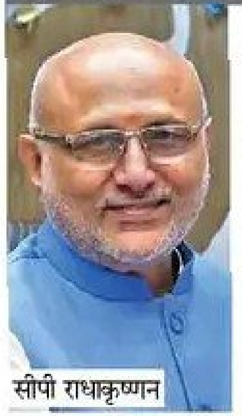

सीपी राधाकृष्णन

- 67 साल के चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक हैं।
- 16 साल में संघ से जुड़े। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने।
- 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने। 1998 में पहली बार कोयंबटूर सीट से सांसद।
- 1999 में फिर चुनाव जीते। इसके बाद तीन चुनाव हारे।
- 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रहे।
- 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे।
- नदियां जोड़ने, समान नागरिक संहिता के लिए 93 दिन में 19 हजार किमी लंबी यात्रा निकाली।
- ओबीसी समुदाय के नेता हैं। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का 'मोदी' कहते हैं।

▶ मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष का आभारी हूं। इस विश्वास से अभिभूत हूं। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करता रहूंगा। **- सीपी राधाकृष्णन**

▶ तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर काम करने वाले राधाकृष्णन ने सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सेवा की। उनके चयन से खुशी है। **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

भास्कर इनसाइट

8 महीने बाद तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव, ऐसे में डीएमके के लिए धर्मसंकट

सुजीत ठाकुर | नई दिल्ली

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम तय कर डीएमके पर स्ट्राइक की है। तमिलनाडु में करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। डीएमके विरोध करती है तो भाजपा और उसकी सहयोगी अन्नाद्रमुक इसे राज्य में चुनावी मुद्दा बनाएंगी। दूसरी ओर, ओबीसी (गौंडर) समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन का विरोध कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। राधाकृष्णन दो बार कोयंबटूर सांसद रहे, इसलिए तमिलनाडु में अच्छी सियासी पकड़ है। झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल होने से, दोनों राज्यों के दलों से भी संबंध अच्छे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र-झारखंड में भी इंडिया के कुछ घटक दल उनके पक्ष में जा सकते हैं। आरएसएस के करीबी नेता का चयन करके भाजपा ने उन्हें भी साध लिया है, जो बाहरी नेताओं को बड़े पदों पर बैठाने से असहज रहते थे।

मंडे मेगा स्टोरी बलूचिस्तान के खनिजों के लिए पाक आर्मी चीफ मुनीर के साथ वार्ता के बाद

अब ट्रम्प म्यांमार की सैन्य तानाशाही पर मेहरबान; सेमीकंडक्टर के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजर

भास्कर न्यूज़, न्यूयॉर्क / नेप्यीडॉ | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने म्यांमार के सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग ह्लाइंग से जुड़े कई कारोबारियों और कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाए हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब वहां हिंसा और दमन बढ़ रहा है। अमेरिका ने उन कंपनियों को भी राहत दी है जो सीधे हथियार निर्माण और सैन्य सप्लाई से जुड़ी रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे 'शर्मनाक' बताते हुए ट्रम्प के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रम्प का यह फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि चीन को म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स हासिल करने से रोकने से जुड़ा हुआ है। **क्या है म्यांमार की सैन्य तानाशाही पर ट्रम्प के मेहरबान होने की पूरी कहानी।**

ट्रम्प के प्रतिबंध हटाने का विरोध क्यों?: मानवाधिकार संगठन बोले- ये अमेरिका का विनाशकारी फैसला है

- ट्रम्प प्रशासन ने म्यांमार के सैन्य तानाशाह जनरल मिन से जुड़ीं 3 कंपनियों और 4 लोगों से प्रतिबंध हटाए। इसमें केटी सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स व इसके सीईओ जोनाथन म्यो क्याव थॉन्ग, म्यांमार केमिकल एंड मशीनरी कंपनी, सटैक टेक और इनके मालिक शामिल हैं। कंपनियों के मालिक टिन लट्ट मिन को भी राहत दी है।
- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम को 'शर्मनाक' और 'विनाशकारी' बताया है। बर्मा कैंपेन यूके की कार्यकारी निदेशक अन्ना रॉबर्ट्स ने कहा, 'सेना अत्याचार करती है, प्रतिबंधों को कड़ा होना चाहिए। चौंकानेवाली बात यह है कि उन कंपनियों पर से रोक हटा दी गई है जो सेना को हथियारों की आपूर्ति में मदद करती हैं।

सेना पर बैन क्यों लगे थे?: 2015 के आम चुनाव में भारी बहुमत से सू की जीतीं थीं, 5 साल बाद फिर तख्तापलट

म्यांमार में करीब 53 साल के सैन्य शासन के बाद नवंबर 2015 में आम चुनाव हुए। इनमें आन सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को बहुमत मिला। उन्होंने 5 साल (अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2021 तक) स्टेट काउंसलर के रूप में सत्ता संभाली। लेकिन 1 फरवरी 2021 को मौजूदा सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने फिर से तख्तापलट कर दिया। सू की को नेप्यीडॉ में नजरबंद रखा है। तत्कालीन बाइडेन सरकार ने मिन और अन्य सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

आन सान सू की

म्यांमार में रेयर अर्थ मिनरल्स कितने?: चीन के कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा हिस्सा म्यांमार से आया था

- 2023 में चीन के कुल रेयर अर्थ उत्पादन का लगभग 57% हिस्सा म्यांमार से आया था। 2023 में चीन की घरेलू उत्पादन कोटा (41,000 टन) था। अमेरिका इस सप्लाई चेन को तोड़कर म्यांमार के माइनिंग में अपना दखल चाहता है।
- म्यांमार का कचिन प्रांत चीन की सीमा पर रेयर अर्थ खनन का बड़ा केंद्र है। 2021 के बाद से यहां अनियंत्रित खनन हुआ है। 2023 में खदानों की संख्या 180 से बढ़कर 300 हो गई। म्यांमार में डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे तत्व निकलते हैं। ये हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने में प्रयोग होते हैं, जो ईवी, सेमीकंडक्टर, विंड टर्बाइन और सैन्य हथियारों (मिसाइल, ड्रोन, पनडुब्बियों) के लिए जरूरी हैं।

ट्रम्प क्या चाहते हैं?: म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा हिस्सा चीन की बजाय अमेरिका को मिले

- म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स खनन पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है। ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक हिस्सा चीन की बजाय अमेरिका को मिले। रणनीति यह है कि सप्लाई चेन में सीधे प्रवेश लेकर चीन पर निर्भरता घटाई जाए और अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए।
- म्यांमार का सैन्य शासन दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में है ताकि उसकी वैधता को स्वीकार्यता मिल सके। तानाशाह प्रमुख मिन राष्ट्रपति ट्रम्प से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जुलाई की शुरुआत में म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो मिन ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रम्प की प्रशंसा की थी।

सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग ह्लाइंग

उधर, मुनीर बोले... पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना; इससे हम समृद्ध देश बन जाएंगे

इस्लामाबाद | पाकिस्तान में तेल के बड़े भंडार के दावों और पाक अधिकारियों की अनभिज्ञता के बाद पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने नया राग छेड़ा है। मुनीर ने कहा कि देश के पास 'रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना' है, जिससे कर्ज कम होगा और पाकिस्तान समृद्ध देशों में शामिल होगा। उन्होंने रेको दिक खनन प्रोजेक्ट को भी खजाना भरने का साधन बताया। यह बयान तब आया जब अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान के खनिज भंडार में रुचि दिखाई, क्योंकि अमेरिका चीनी सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है।

File affidavit in seven days or apologise: EC to Rahul Gandhi

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar refuses to provide machine-readable voter lists and CCTV footage of polling, citing voter privacy concerns; he says if complaints are not filed within 45 days of poll results, parties must file affidavits

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

The Election Commission of India on Sunday doubled down on its demand that Leader of Opposition Rahul Gandhi submit an affidavit stating his allegations of voter roll manipulations in a Karnataka Assembly constituency.

In his first press conference since assuming office, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar did not name the Congress leader, but issued him an ultimatum to submit the signed affidavit within seven days or apologise to the nation.

The CEC refused the Opposition's demands to publish a machine-readable voter list and to provide CCTV footage of the voting process, claiming that both measures would violate voter privacy.

Combative CEC

This comes 10 days after Mr. Gandhi alleged deliberate, large-scale discrepancies in the voter rolls of the Mahadevapura Assembly segment of the Bangalore Central Lok Sabha constituency, which the BJP won in the 2024 general election. Following his allegations, the Chief Electoral Officers of Karnataka, Maharashtra, and Haryana had asked him to submit his allegations under oath, which he has refused to do.

Asked why the EC has not taken *suo motu* cognisance of the allegations, a combative CEC said: "If accusations are made against 1,50,000 people, then should all these voters be given notices without any evidence?"

"You have to give an affidavit or apologise to the nation. If within 7 days affidavit is not given, then it means allegations are wrong," he said.

'No discrimination'

However, Mr. Kumar did not reply to a question on why BJP MP Anurag Thakur – who has made similar allegations of voter roll discrepancies in the Rae Bareli Lok Sabha constituency, which is represented by Mr. Gandhi – was not asked to submit an affidavit as well.

> You (Rahul Gandhi) have to give an affidavit or apologise to the nation. If within seven days affidavit is not given, then it means allegations are wrong

> If accusations are made against 1,50,000 people, then should all these voters be given notices without any evidence?

GYANESH KUMAR
Chief Election Commissioner

To another question on why a complaint filed by the Biju Janata Dal in Odisha about last year's Lok Sabha election had not been probed, Mr. Kumar clarified that the complaint was not made under oath, adding that the 45-day limit for complaints has also passed. He had a similar response to a complaint filed by Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav.

The CEC began the press conference by asserting that the EC cannot discriminate among political parties, insisting that it considers ruling and Opposition parties as equal.

He said that it was an insult to the Constitution if election petitions are not filed within 45 days, but allegations of "vote *chori*" (vote theft) are later raised.

"According to law, if errors in the voter list are not reported in time, if an election petition is not filed in the High Court within 45 days of a voter choosing their candidate, and then misleading attempts are made to confuse people by using wrong words such as 'vote theft', then what else can this be if not an insult to the Constitution of India?" he asked. "More than one crore employees are engaged in the election exercise. Can 'vote *chori*' happen in such a transparent process?" he added.

Mr. Kumar sought to dismiss any doubts about the 2024 election. "How can someone steal votes" in such a scenario, he asked, adding that "neither the EC nor any voter is afraid of such baseless accusations".

On accusations made by the Opposition regarding the Maharashtra Assembly election, he said: "When the results came, they remembered that the rolls are wrong? No objection with evidence has been filed against any voter with the Maharashtra CEO. The elections happened eight months ago. Why no election petition was filed?"

VEILED THREATS: CONG.
» **PAGE 5**
'DELETED NAMES ON SITE'
» **PAGE 5**

Biodiversity everywhere is ordered by a common 'hidden' pattern

A new study has found that biodiversity is organised like an onion: with dense, unique biodiversity at the centre and grading outward towards porous, mixed margins; these findings could reveal insights into the basic forces that assemble nature's living mosaics and show conservationists where protection could have the biggest payoff

Hirra Azmat
Vasudevan Mukunth

For almost two centuries, biologists have divided the earth into large biogeographical regions. Each region hosts a unique mix of species shaped by its own history, climate, and barriers, such as oceans and mountains. Because those histories differ, many scientists assumed the inner layout of species inside every region would be idiosyncratic – that South America's biodiversity, for example, would organise itself in a very different way from Africa's.

At the same time, global rules clearly exist. Tropical zones almost everywhere teem with life while polar zones host far fewer species. The authors of a new study wondered: could there also be a universal rule inside each biogeographical region, one that transcended continents, oceans, and even entire branches of the tree of life?

Answering that question could reveal the basic forces that assemble nature's living mosaics and show conservationists where protection could deliver the biggest payoff.

A newly uncovered core rule turns the earth's messy quilt of species' ranges into something organised in layers. DAVIDVRAJU (CC BY-SA)

Peeling the onion

A new study, authored by scientists in Spain, Sweden, and the UK, reported just such a pattern in the July edition of *Nature Ecology & Evolution*.

According to University of Kashmir Department of Botany assistant professor Irfan Rashid, the study provides a rare, large-scale, data-backed confirmation of a general rule in biogeography.

In search of a hidden rule, the researchers cast an exceptionally wide net. They studied more than 30,000 species, including birds, mammals, amphibians, reptiles, rays, dragonflies, and trees. Information about the species' ranges came from global databases such as the IUCN Red List, BirdLife International, and US Forest inventories. The team also tiled the earth's surface into thousands of cells of equal area – each about 111 sq. km for most land animals, for example – and recorded all the species living there.

Then the researchers used a network analysis tool called Infomap to group those cells together whose species frequently co-occurred. Each cluster thus became a biogeographical region, and the species most tied to that region were tagged as characteristic, i.e. as belonging to its core community. Species that spilled over from neighbouring regions were called non-characteristic.

Finally, they took snapshots of four types of diversity in every cell: species richness (how many characteristic species live here), biota overlap (what fraction of species are non-chracteristic); occupancy (how widely do characteristic species range); and endemicity (how much of each characteristic species' range is confined to that region alone).

With these four numbers in hand, the researchers ran a clustering algorithm on all the cells. If biodiversity organised itself differently among different kinds of organisms, cells from birds would cluster apart from cells from mammals, and so on. If a common rule existed, however, the algorithm would lump cells from many different taxa together.

This is how the researchers were eventually able to split the world into seven repeating biogeographical sectors. More importantly, they found that the sectors appear again and again inside every major region and for every taxonomic group, lining up in a remarkably orderly pattern.

The core hotspots were highly rich, highly endemic, and had almost no foreign species. The next inner layers were still species-rich but had slightly more endemic species and slightly more widespread species. The middle layers had no richness and also had some non-characteristic species. Finally, the transition zones were species-poor and packed with wide-ranging generalists from multiple regions.

That is, biodiversity everywhere was organised like an onion: with dense, unique biodiversity at the centre and grading outward towards porous, mixed margins.

The researchers also found that in 98% of region–taxon combinations, temperature plus rainfall models could predict which sector a cell belonged to. This implied that only species that could tolerate the local conditions could survive in a given layer.

> The study provides a strong basis for understanding broad ecological trends
>
> **AMIT CHAWLA**
> PRINCIPAL SCIENTIST AT THE CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY (IHBT), PALAMPUR

Further, the species that inhabited the outer layers were also usually subsets, not replacements, of inner layer species. That is, moving outward from the core, there were fewer specialist species rather than entirely different specialised species.

"The study provides a strong basis for understanding broad ecological trends," Amit Chawla, Principal Scientist at the CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT) in Palampur, Himachal Pradesh, said. "It shows how biodiversity tends to spread outward from regional hotspots, and how environmental filters like elevation or climate allow some species to move while blocking others."

Geographical gaps

In a time of climate uncertainty, understanding how species are spread can help make smarter decisions about what to protect and where. In the Indian Himalayas, for example, this could mean looking beyond traditional protected areas and focusing on key habitats, altitudinal zones, and natural corridors.

"We need to look at how changes in rainfall or temperature are affecting biodiversity along mountain slopes," Chawla said. "Small experiments that simulate these changes can give us important insights."

"The Himalayas are already experiencing rising temperatures and shifting rainfall and are at the frontlines of this change. Studies like this one offer a useful lens to understand the big picture," Asif Bashir Shikari, professor of genetics and plant breeding at the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, said.

Finally, Chawla did point out that while the study was global in scope, it had some geographical gaps. "For instance, groups like dragonflies in Eurasia and trees in North America were studied only in limited regions. The conclusions for these taxa could have been stronger with more comprehensive global datasets," he said.

He added that some biodiversity-rich regions in the tropics and Global South, including parts of India, were underrepresented for certain taxa, underscoring the need for region-specific research to complement these global findings.

In sum, the newly uncovered core-to-transition rule turns the earth's messy quilt of species' ranges into something organised in layers. By identifying how environmental filters shape these layers, the study could give conservationists a sharper lens through which to understand and protect the living planet.

(Hirra Azmat is a Kashmir-based journalist who writes on science, health, and environment. azmathirra@gmail.com, mukunth.v@thehindu.co.in)

THE GIST

- Researchers tiled the earth into cells and recorded the species there. Then a tool called Infomap grouped together those cells whose species co-occurred. Species were tagged as characteristic or non-characteristic. Finally, they took snapshots of four types of diversity in every cell

- Researchers then ran a clustering algorithm on all the cells. If biodiversity organised itself differently among different organisms, cells from birds would cluster apart from mammals, and so on. Thus they split the world into seven sectors. The sectors appear repeatedly inside every major region and for every taxonomic group, lining up in an orderly pattern

- It was found that temperature plus rainfall models could predict which sector a cell belonged to. This implies that only species that can tolerate local conditions can survive in a given layer. Moving outward from the core, there were fewer specialist species rather than entirely different species. The study shows that environmental filters allow some species to move while blocking others

A conservation manual, drafted by the ordinary citizen

In his Independence Day addresses delivered from the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi has been exhorting fellow citizens to preserve the memory of those who overthrew colonial rule. Even as his reminders have been timely, his tactics – enumerating a few freedom fighters' names and including some of their words in his speeches – are as well-worn as the Archaeological Survey of India's (ASI) approach to conserving the nation's built heritage. With a few exceptions, the ASI has largely been content with selecting monuments, isolating them, repairing them and occasionally polishing them. Given the enormity and complexity of India's past and the risk of large sections of it fading from our collective consciousness, it is time to articulate a more thoughtful and holistic approach to the conservation of ASI monuments.

Acknowledging that the current frameworks informing conservation are the result of certain historical circumstances is important. Driven by a conviction that edifices, if properly analysed, can unlock histories of communities and thus allow for governing them more effectively, colonial officers located and catalogued pillars, rock-cut caves, *stupas*, temples, mosques, citadels, water reservoirs, and other edifices, promulgated historical preservation laws, and prescribed procedures for maintaining their structural integrity. John Marshall's *Conservation Manual* (1923) advocated extensive repair of ancient monuments and reshaping their immediate surroundings into gardens.

Marshall's handbook continues to inflect the preservation of about 3,600 ASI sites, along with new laws, amendments, and provisions of international agreements. Notwithstanding these efforts, field surveys, audit reports, and court rulings establish that many protected monuments are falling apart. Recommendations of a conservation policy enunciated in 2014 are being irregularly followed. Not surprisingly, the government has begun to invite corporations to adopt monuments.

A road map for conserving monuments

Studying the writings of modern India builders is one way to begin articulating a new approach to conserving monuments. Consider lessons provided by Sarvodaya, Mahatma Gandhi's transcreation of a collection of essays by John Ruskin, a Victorian art critic. His rendering accentuated the art critic's advocacy of improving the social condition of all individuals irrespective of their backgrounds, discussed the importance of all vocations, and endorsed his admiration of craftspersons and their labour, even as it critiqued Ruskin's valorisation of Britain's imperial ambitions. Might the lessons that Gandhi learned and promoted inspire the ASI's new conservation manual to propose the following: when an edifice is conserved not only is its structural fabric to be tended, but the lives of all those who live around it and visit it are to be improved; and interpretive materials at an edifice should enable visitors to appreciate its builders' sophistication, inventiveness, and resilience.

Nachiket Chanchani

is an Associate Professor in the Department of the History of Art at the University of Michigan, Ann Arbor, U.S.

There needs to be a more thoughtful and holistic approach to the conservation of the Archaeological Survey of India's monuments

Conservation is a shared concern of contemporary practitioners of diverse disciplines including translators, health-care professionals, wildlife biologists, mycologists, and economists. By convening dialogues among and between these experts at various venues, listening to how they comprehend terms such as repair, preservation, and restoration and observing how audiences respond to them, the ASI can identify more principles of their new conservation manual.

Translators today are attentive to the style and mood that the authors of source texts have sought to nurture and are grasping how sentences are formed and meanings generated in unalike languages. They are recognising that connotations change over time. Thus, their outputs are intricate works in dialogical relationships with assorted pasts, and not obsequious reproductions of texts initially written in other languages. Can such viewpoints inspire the ASI conservation manual to recommend that archaeologists acknowledge their distance between the deep past and contemporary moment and make their physical interventions of a monument's fabric clearer for visitors to discern? Contemporary translators sophisticated thinking of a particular language aptness to render anew a certain text may also be used to inform a clause in the new manual: that periodic reviews be undertaken of the aptness of preservation materials to ensure that they do not harm historical fabrics.

Varied perspectives are important

Humans preserve themselves by saving memories. Listening to divergent perspectives allows memories to be exercised and sustains their propagation. Such insights should inspire the ASI to study how visitors are using protected monuments today and craft conservation principles thereafter. One way to do so would be to offer visitors opportunities to participate in open-ended conversations about their experiences.

Wildlife biologists are also thinking about protection. They reason that supporting a range of interactions occurring among and between sundry biotic and abiotic elements in an ecosystem and exchanges between networks are more efficacious strategies for restoring waning populations than safeguarding individual animals. Following this line of reasoning, might the ASI conservation manual recommend that archaeologists pay more attention to linkages between monuments and water bodies, fields, deserts, forests and settlements around them and deliberate whether certain boundary walls may be dismantled.

Mycologists have found that fungi are far from unsettling sights. Fungi are powerful agents that break down organic matter, form mutually beneficial relationships with plants including helping them access nutrients, cause diseases in humans but also provide medicines, and help produce food. Such discernments can stimulate the ASI's manual to encourage the conservation of thousands of small, half-forgotten ancient monuments strewn across the country. Old city walls, cisterns, cenotaphs and dovecotes can have multiple benefits for communities living around them including securing neighbourhoods, recharging ground water aquifers, bringing visitors who might boost local economies, providing habitats and creating public spaces.

Finally, contemporary economists' findings may also be generative. They have shown that value is produced by how things work and not just by their appearance. Following this dictum, the conservation manual may propose that it is more important for archaeologists to restore a *haveli's* natural ventilation systems than to regularly repaint its façade. Emphasising a particular resource's scarcity is another way in which value is created. Thus, further research should be undertaken to advance our knowledge of what makes ASI monuments sites of national significance. The new knowledge be used to justify larger budgets for their protection. The economic concept of creative destruction as an impetus for growth may also be utilised. For example, it can guide the transformation of old temples submerged in the reservoirs of large dams into laboratories for developing and testing technologies to document underwater sites and forge innovative alliances between historians, geologists and marine biologists.

The citizen's role

In a country as diverse as ours, conservation's meaning and value are always going to be positional and contested. Thus, all of us as ordinary citizens can help shape a new conservation manual by becoming more aware of our own locations and actions. We can also assist by further educating ourselves. Learning to read the language of the stones that monuments are built of, will allow us to listen to stories they tell and amplify largely silenced voices. We will also be able to glean builders' biases and use monuments as mirrors to confront our prejudices. Ultimately acquiring such literacy will empower us to discover India as a monument without walls and preserve ourselves as we shape a new future.

What has been the impact of ethanol blending?

How are petrol vehicle owners reacting to the E20 mandate? How environmentally friendly is India's dependence on sugarcane for ethanol? How has the U.S. reacted to India's booming ethanol economy? Why has the adoption of EVs in India been much slower compared to other large economies?

EXPLAINER

Kunal Shankar
S. Hariharan

The story so far:

E20 petrol, which contains 20% ethanol and is being sold by Indian oil refiners, has been much in the news lately. India has achieved its target to blend 20% ethanol per litre of fuel five years ahead of the target under the National Policy on Biofuels. Ethanol blending in India rose from just 1.5% in 2014 to 20% in 2025, backed by the government's strong fiscal incentives to the sugarcane industry. While the government says ethanol blending achieves a range of goals such as cutting greenhouse gas emissions, bolstering farmers' incomes and reducing India's oil import bill, its benefits to the environment require closer scrutiny.

New fuel: Farmers load freshly harvested sugarcane into a tractor trolley during the harvesting season, in Karad, Maharashtra, on December 15, 2024. PTI

How are vehicle owners reacting to this change?

Vehicles sold in India from 2023 come with E20 stickers, indicating compatibility with 20% ethanol blended petrol. Additionally, manufacturers have addressed the concerns of those who own older vehicles. Hero Motocrop says in its website, "The material composition such as rubbers, elastomers and plastic components that are directly exposed to fuel also need to be changed to E20 compatible materials."

However, according to LocalCircles, two in three petrol vehicle owners are against the E20 mandate. Only 12% of the 36,000 people surveyed across 315 districts are in favour of the switch. Critics cited a drop in mileage and increased maintenance costs. The survey urged the Union government to allow consumers to choose the type of fuel they want.

While the Centre admitted to a "marginal drop" in engine efficiency, it said this "can be further minimised through improved engine tuning and use of E20-compatible materials." Minister Hardeep Singh Puri has called the consumer angst a "vilification campaign" facilitated by "vested, economic interests". While the Union government attempts to defend its E20 policy, its own think tank, the NITI Aayog, has urged the government "to compensate the consumers for a drop in efficiency from ethanol blended fuels", by way of "tax incentives on E10 and E20 fuel".

According to the Minister, "since 2014-15 India has already saved more than ₹1.40 lakh crore in foreign exchange through petrol substitution." But has the benefit been passed to the end consumer?

An analysis by *The Hindu* showed that Coal India Ltd, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL), and Gas Authority of India Ltd collectively contributed ₹1.27 lakh crore, or 42.3% of the total ₹3 lakh crore dividends the Union government received from non-banking Public Sector Undertaking (PSUs) between 2020-21 and 2024-25. IOC and BPCL together saw a 255% rise in their dividend payouts since 2022-23 and a 65% decrease in oil prices. However, the two PSUs only passed on a 2% decrease in petrol prices to the public.

What about the impact on agriculture?

Sugarcane-based ethanol supply has grown from 40 crore litres in FY14 to nearly 670 crore litres, derived from about 9% of total sugar output, in FY24. The Union government says it has paid "over ₹1.20 lakh crore to farmers" since FY15. But how environmentally friendly is India's dependence on sugarcane for ethanol?

About 60-70 tonnes of water is required to cultivate one tonne of sugarcane. Many sugarcane growing regions in India do not receive the 1,500 to 3,000 millimetre rainfall that is necessary for the crop's optimal growth. This leads to groundwater extraction and unsustainable irrigation methods. A 2023 Central Groundwater Board report says that sugarcane growing districts in Maharashtra extract more groundwater than nearby regions. Distress among sugarcane growers in that State has been widely reported. Unsustainable agriculture practices accelerate land degradation. The Desertification and Land Degradation Atlas of India 2021 found that almost 30% of India's land is degraded. The water intensive nature of sugarcane and the impact on ground water reserves at a time of extreme weather has been absent from the discussion on ethanol-blended petrol.

The Centre, however, says it is looking to diversify ethanol supplies. The Food Corporation of India's rice allocation for ethanol jumped to a record 5.2 million metric tonnes, which is about 3.6% of output, from less than 3,000 tonnes allocated last year. Similarly, in 2024-25, over 34% of corn output was diverted for ethanol production. This diversion forced India to import about 9.7 lakh tonnes of corn during 2024-25 – a six-fold increase over the previous year's 1.37 lakh tonnes.

Despite diversification efforts, area under sugarcane cultivation this year is estimated to be 57.24 lakh hectare against 57.11 lakh hectare last season. The assured payment mechanism for sugarcane, the Fair and Remunerative Pricing, is the key reason farmers bet on the crop as a source of stable income. While this rise is marginal, an analysis by the OECD-FAO says that 22% of India's sugarcane will be used for ethanol production by 2034.

India's booming ethanol economy has also come under the gaze of the U.S. The Trump administration is pushing India to relax restrictions to its ethanol imports. The 2025 National Trade Estimate report noted India's policy as a significant "trade barrier." Import relaxation could potentially undermine years of investment and capacity building in ethanol production. The Indian Sugar Mills Association has urged the government to maintain the restrictions.

Will it affect the transition to EVs?

The Ministry of Petroleum and Natural Gas said the shift to ethanol-blended petrol "has helped India reduce carbon dioxide emissions by 700 lakh tonnes." Shifting to EVs, however, will achieve far higher rates of emissions reductions and speed up transport's decarbonisation, which is the third largest carbon emitting sector globally after energy and industry. The success of cities like Beijing in cutting air pollution is mainly due to the rapid adoption of EVs. Of course, this switch has to be backed by renewable energy rather than coal, to aid in decarbonising transport.

Adoption of EVs has been much slower in India when compared to other large economies like the U.S., the European Union and China. About 7.6% of vehicle sales in 2024 was electric. Sales of EVs have to increase by over 22% in the next five years to reach the government's own target of 30% by 2030.

Another challenge to wider EV adoption in India is its dependence on Rare Earth Elements (REE). According to the Ministry of Mines, before China's export curbs were imposed, only 2,270 tonnes of REEs and compounds of REEs were imported in 2023-24. But this relatively lower level is critical for the industry to sustain the current level of EV production. The production and processing of many REEs is geographically concentrated in China, making global supply vulnerable to several risks.

The automotive industry has also sounded alarm bells about the disruption in rare earth supply. India's largest carmaker Maruti Suzuki reduced its near-term production targets for its new EV, e-Vitara, attributing it to delays in receiving rare earth magnets. Other manufacturers too are bracing themselves for disruptions.

Crisil Ratings Senior Director Anuj Sethi has said, "The supply squeeze comes just as the auto sector is preparing for aggressive EV rollouts." The recent detente in bilateral relations with China might help the industry to address the crisis in the short term. The Union government is engaged in diplomacy with Beijing to address the rare earth supply crunch, mainly germanium.

Going forward, there is uncertainty on whether the Centre wants to push ahead with ethanol blending beyond 20%. While Minister Puri said the government will push for blending beyond 20%, the Union government in March said that there has been no decision yet.

To know more, please scan the link to watch The Hindu's video explainer newsth.live/ethanolblending

THE GIST

- Vehicles sold in India from 2023 come with E20 stickers, indicating compatibility with 20% ethanol blended petrol. Additionally, manufacturers have addressed the concerns of those who own older vehicles.

- The Ministry of Petroleum and Natural Gas said the shift to ethanol-blended petrol "has helped India reduce carbon dioxide emissions by 700 lakh tonnes."

- India's booming ethanol economy has also come under the gaze of the U.S. The Trump administration is pushing India to relax restrictions to its ethanol imports.

SC can't treat Governors as 'aliens', says govt.

A Governor is not a mere 'post office', but a check on 'hasty legislation' by the States, Centre tells SC ahead of hearing on Presidential Reference; Solicitor-General stresses that Articles 200 and 201 deliberately omit any time limit for Governors or President to act on State Bills, and judicially imposing deadlines amounts to rewriting the Constitution

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court cannot treat Governors as "aliens" or "foreigners" on whom timelines can be imposed and whose discretion does not count, the Union government has said in a submission. It said that a Governor was not a mere "post office", but a check on "hasty legislation" by the States.

The submission by the Centre, made in a note authored by Solicitor-General Tushar Mehta, is part of the record in a Presidential Reference to be heard by a Constitution Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai from Tuesday. The reference stems from an April judgment by a two-judge Bench, imposing a three-month deadline on the Governors and the President when dealing with State Bills, and declaring that Governors could not use their discretion in dealing with these Bills.

Though Tamil Nadu submitted that Presidential References could not be used to reopen or nullify the top court's judgments, Mr. Mehta maintained that the April ruling had trespassed upon a zone exclusive to the President and Governors.

'No existing provision'

He submitted that neither Article 200 (Governor's power to assent to State Bills) nor Article 201 (President's power to consider State Bills referred to her by the Governor for consideration) provided any specific time limit.

"The absence of any express time limit in Articles 200 and 201 is a deliberate and conscious constitutional choice. The judicial direction of imposition of any timeline would amount to an amendment to the Constitution," Mr. Mehta emphasised.

"Governors are not to be treated as alien/foreigner in the federating units of the Union. Governors are not just emissaries of the Centre.... Governors are constitutional actors," Mr. Mehta submitted.

> Governors are not just emissaries of the Centre. The Governors possess democratic legitimacy through indirect democratic representation. Governors are appointed by the President on the aid and advice of the Council of Ministers... Governors are constitutional actors
>
> Submission by the Centre

The submission is part of the Presidential Reference over a judgment in a plea against the Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's delay in clearing State Bills.

The Centre's law officer noted that "the Governors possess democratic legitimacy through indirect democratic representation. Governors are appointed by the President on the aid and advice of the Council of Ministers." He argued that the nature of gubernatorial assent has a unique duality of character. Though the assent is given by an apex executive authority, the act itself is legislative in nature. The Supreme Court's approach ought to have been more calibrated, he said.

The note asked whether the court could invoke Article 142 and assume powers under Article 200 and 201 to grant deemed assent to 'delayed' State Bills.

"The alleged failure, inaction, or error of one organ does not and cannot authorise another organ to assume powers that the Constitution has not vested in it. Article 142 does not empower the court to create a concept of 'deemed assent', turning the constitutional and legislative process on its head," Mr. Mehta said.

He argued that a Governor was not precluded from exercising discretion under Article 200 to grant assent, withhold assent, reserve a Bill for the President's consideration, or return it to the Legislative Assembly, even in the absence of aid and advice to that effect.

"The Governor's assent cannot be a mechanical process... Situations may arise where the Governor may need to take a view independently of the Council of Ministers," Mr. Mehta argued.

Moreover, the Union government said that directing the President to consult the Supreme Court under Article 143 in case of any doubts about State Bills would effectively turn a constitutional prerogative into a judicial mandate.

"An absolute discretion lies with the President to seek advice. The term 'consult' means the President is not bound to do so," Mr. Mehta submitted.

In its written submissions, Tamil Nadu, represented by senior advocate P. Wilson, insisted that questions on the powers of the President and the Governors as regards State Bills have already been settled by the April 8 judgment, adding that entertaining the Reference now would erode the finality attached to Supreme Court judgments under Article 141 of the Constitution. Tamil Nadu submitted the court was not bound to answer every Presidential Reference made to it.

The April 8 judgment was pronounced by a Supreme Court Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan in a petition filed by the Tamil Nadu government, which had challenged Governor R.N. Ravi's delay in clearing 10 re-passed Bills and his subsequent action to reserve them for consideration by the President.

The two-judge Bench had thrust a three-month deadline on State Governors and the President to deal with State Bills sent to them for consideration. It had concluded that Governors enjoyed no discretion while dealing with these Bills, and were totally bound by the 'aid and advice' of the State Legislature concerned. The Division Bench had even invoked Article 142 of the Constitution to grant 'deemed assent' to 'delayed' State Bills. The April 8 judgment had further directed that the President must seek advice from the SC under Article 143 in case of any vexing State Bills.

REFERENCE CHALLENGED
» PAGE 2

What are the challenges confronting the EC?

Why is the Election Commission of India in the eye of a storm? What are the allegations raised by the Opposition? What happened after the draft electoral roll was released in Bihar? What is the Supreme Court's interim order? How are migrant voters going to be affected by the SIR?

Sreeparna Chakrabarty

The story so far:

At a press conference on August 7, Leader of the Opposition Rahul Gandhi accused the Election Commission (EC) of massive electoral roll manipulations in Mahadevapura Assembly constituency in Karnataka. Mr. Gandhi's presser capped a series of allegations of deliberate voter roll discrepancies by the EC beginning with the Maharashtra Assembly polls. This, coupled with the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar, which is under judicial scrutiny, has put the poll body in the eye of a storm.

What is the mandate of the EC?

The Election Commission of India is a permanent constitutional body. The Constitution has vested in the EC the superintendence, direction and control of the entire process for conduct of elections to Parliament and the legislature of every State, and to the offices of President and Vice-President of India. Originally, the commission only had a Chief Election Commissioner (CEC). It was expanded to include two Election Commissioners (ECs).

Why has there been a controversy about the appointment process?

Parliament passed a new law governing appointments to the EC, namely the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023. In accordance with the new law, the ECs are selected by a three-member selection committee, comprising the Prime Minister, a Union Minister and the Leader of the Opposition. The Opposition had objected to this, saying the committee gave little room for dissent as the Prime Minister and the Union Minister are part of the government and could rule 2:1 in favour of their candidate.

The ongoing monsoon session of Parliament has been virtually paralysed over demands for a discussion on the Bihar SIR exercise

In protest: Rahul Gandhi and other INDIA bloc leaders during their march to the Election Commission from Parliament, in New Delhi on August 11. ANI

Why is the EC's role in the spotlight?

Last year, the Maha Vikas Aghadi (MVA) alliance had alleged that lakhs of new voters had been added to Maharashtra's electoral rolls in the time period between the Lok Sabha polls in May and the Assembly elections in October. The Congress had made the same allegations about Haryana, and later the Aam Aadmi Party alleged that voter rolls were tweaked in Delhi before Assembly polls. Even as the EC was grappling with these claims, CEC Gyanesh Kumar announced the SIR in Bihar which aims at cleaning up electoral rolls. The EC said the SIR exercise will be carried out across the country.

At his press conference, Mr. Gandhi alleged large-scale discrepancies in the Mahadevapura Assembly segment under the Bangalore Central Lok Sabha constituency in Karnataka which he claimed helped the BJP win the seat. Mr. Gandhi said his party had carried out an investigation which spanned over six months before reaching this conclusion. He claimed that the voter list had manipulated entries, including duplicate voters, invalid addresses, and bulk registrations of votes at single locations. Following this, Mr. Gandhi reiterated his demand for machine readable voter rolls to be provided to all political parties for proper verification. The EC stated it has not been providing machine readable or "text-searchable" voter lists for concerns over cyber-security. The Supreme Court (SC) had upheld it in a petition filed by former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath in 2018.

When was a revision announced in Bihar?

On June 24, the EC ordered a SIR of electoral rolls in Bihar, barely five months before the Assembly elections. As per the SIR orders, every voter in Bihar who had not been listed in the 2003 voter rolls would have to submit documents proving their date and place of birth to determine whether they were Indian citizens. Those born after 1987 would also have to submit proof of their parents' date and place of birth.

However, after the completion of the first phase of the SIR exercise, the EC released a draft electoral roll on August 1, which saw a drop in the number of voters in Bihar by 65 lakh. There were 7.89 crore voters registered in the 2025 electoral list before the SIR exercise; after the recount, it slid to 7.24 crore electors. The EC said that most of these 65 lakh "missing" voters have died; are registered in two locations; have migrated out of Bihar; or are untraceable. Civil society organisations, Opposition parties as well as NGOs approached the Supreme Court challenging the SIR process.

What has the SC directed EC to do?

In an interim order on August 14, the Supreme Court directed the EC to publish an enumerated, booth-wise list of the 65 lakh electors not included in the draft roll. A Bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi instructed the EC to provide reasons for the deletion – death, migration, untraceability, duplicate registrations – against each name. The court also asked EC to accept Aadhaar as proof of identity for an elector to include his or her name in the rolls.

"That it has taken the Supreme Court to nudge the EC towards following basic norms of natural justice and fairness in the Bihar SIR exercise reflects poorly on an organisation which takes pride in collecting and counting every last vote. While errors can creep into voter lists over time, the answer to that is not mass disenfranchisement as the EC is attempting," said Alok Kumar Prasanna, Advocate and Co-Founder of Vidhi Centre for Public Policy.

What about migrant voters?

Migrant voters still have to return to the place where they are on the rolls to vote. This is a huge cost and depresses turnout, notes Mr. Prasanna. "There is no simple solution to this currently. The solution will have to be cheap, secure and transparent to work. Solutions which work in richer societies and for richer migrants will not work for poor migrants from States like Bihar," he added.

What has been the political fallout?

After Mr. Gandhi's press conference, the Opposition upped the ante and tried to hold a march from Parliament to the Election Commission headquarters. They courted arrest when stopped. The ongoing monsoon session of Parliament has also been virtually paralysed over demands for a discussion on the Bihar SIR. The government has, however, not conceded to the Opposition's demand. The issue has brought Opposition parties together and protests are likely to continue when Parliament reconvenes on August 18.

"To protect the voters of this country and democracy whatever has to be done we will do," Rashtriya Janata Dal Rajya Sabha MP Manoj Jha told *The Hindu*.

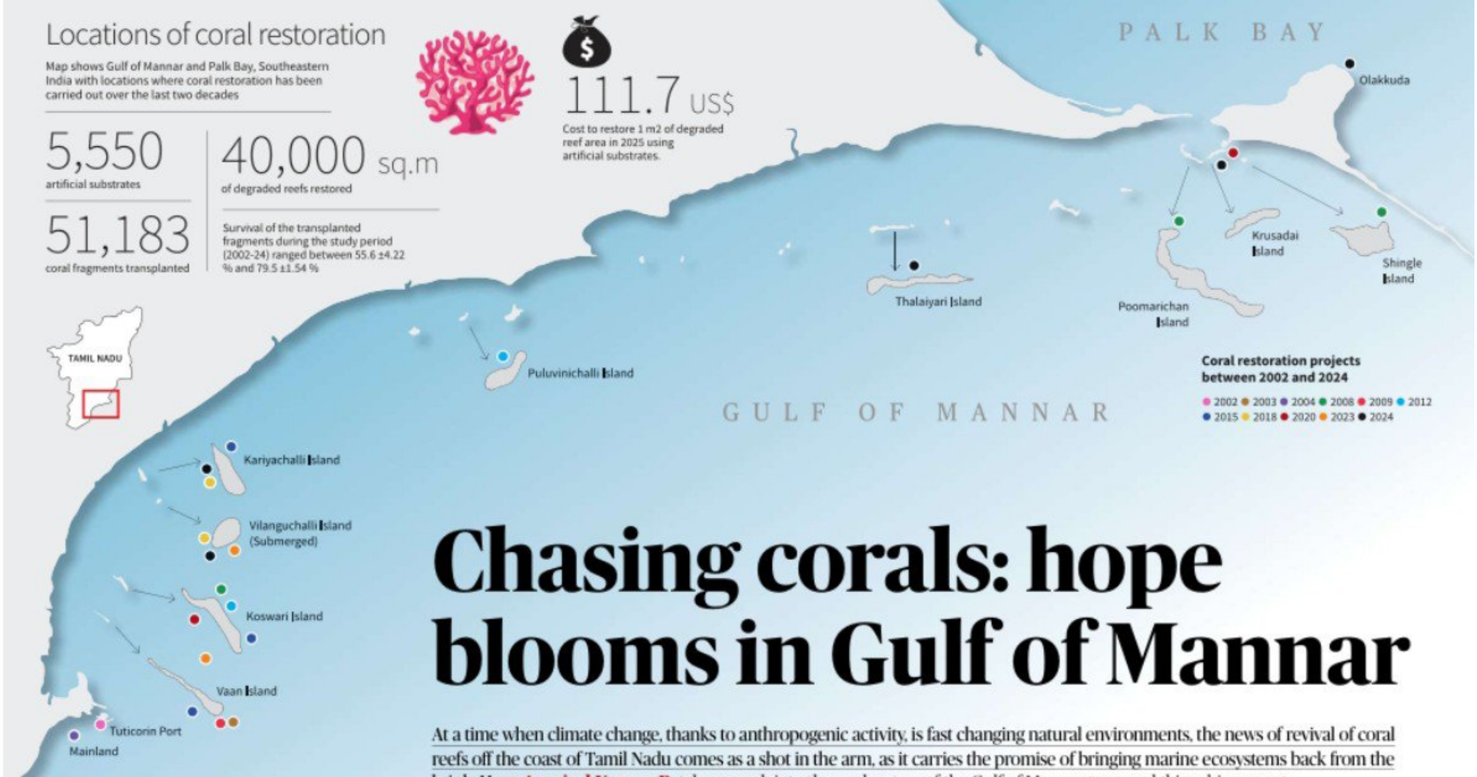

Chasing corals: hope blooms in Gulf of Mannar

At a time when climate change, thanks to anthropogenic activity, is fast changing natural environments, the news of revival of coral reefs off the coast of Tamil Nadu comes as a shot in the arm, as it carries the promise of bringing marine ecosystems back from the brink. Here, **Aravind Kumar B.** takes a peek into the cool waters of the Gulf of Mannar to record this achievement

Coral reefs are the crowning jewels of marine ecosystems. They are not found everywhere; making them rare, limited edition species. Tamil Nadu has its own enchanting coral necklace along the 21 islands dotting the Gulf of Mannar Marine Biosphere. Most of them thrive naturally, many are dead or decaying owing to climate and anthropogenic changes, and a small portion is reviving, thanks to human care.

If planting and restoration of forests itself is a Herculean task, imagine how daunting the revival of coral reefs on the seabed can be. While underwater research is in its primitive stage in India, a dedicated team of scientists from Suganthi Devadason Marine Research Institute (SDMRI), Thoothukudi, has been scuba-diving and scrubbing the seabed for conducting annual surveys over the last two decades, along with Tamil Nadu's Forest Department.

A recent study has highlighted the lessons learnt, successes, challenges, and prospects of long-term coral restoration to mitigate the anthropogenic and climatic impact on the Gulf of Mannar. The study was published in the *Journal of Environmental Management* by J.K. Patterson Edward, G. Mathews, K. Diraviya Raj, Jamila Patterson, Dan Wilhelmsson, and Jagdish Sudhakar Bakan.

Owing to coral mining since the 1960s, the natural substratum had become unstable in the Gulf of Mannar. As the area is not rocky and reefs had developed around low-lying islands, it was decided to use artificial substrates. Initially, stones, clay pots, ropes, cement slabs, fish houses, and concrete frames were tested for coral restoration. Strong currents and waves caused dislocation and fragmentation of artificial substrates, leading to a reduced survival rate. Then, the scientists started using concrete frames. They are made at a site far from the coast and transported to the shore by trucks. Then the frames are taken to the restoration sites on a raft made of bamboo poles or on a small barge that can accommodate up to five tonnes. The substrates are placed on the seabed with the help of ropes tied to the frames and arranged underwater by divers. Then, the frames are arranged at an interval of 1 to 2 metres, leaving enough space for the coral to grow.

Artificial reef modules

Apart from artificial substrates, different types of artificial reef modules have been deployed in the Gulf of Mannar. Triangular artificial reef (TAR) modules were deployed near Vaan Island in 2002 for enhancing fishery potential and biodiversity. They were regularly monitored for coral recruitment. Perforated trapezoidal artificial reef (PTAR) modules were also deployed around Vaan Island for protecting it from soil erosion, enhancing fishery potential, and assisting in coral recovery. A total of 10,600 modules were deployed between 2015 and 2019.

All the transplantation efforts were done by the trained scientific divers of the SDMRI Reef Research Team. To maintain the genetic diversity, 20 coral species were used. Of these species, 11 were from the fast-growing family *Acroporidae* (*Acropora* and *Montipora*) and the rest from other genera and morphotypes. The survival and growth of the transplanted fragments was assessed monthly for a minimum of two to a maximum of five years in different locations.

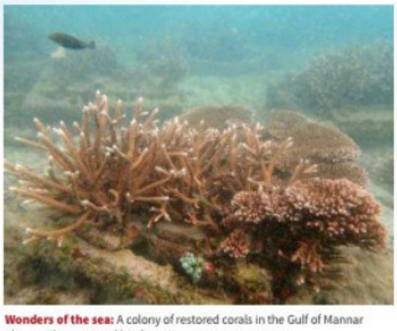

Wonders of the sea: A colony of restored corals in the Gulf of Mannar along with associated biodiversity. SPECIAL ARRANGEMENT

> Formation of a basal disc by the transplanted fragments on the substrate within one or two months was encouraging
>
> **J.K. PATTERSON EDWARD,** SDMRI director

In the past two decades, the SDMRI scientists have transplanted a total of 51,183 coral fragments in the 5,550 artificial substrates and restored an approximate area of 40,000 square metres of degraded reefs in the Gulf of Mannar. "The formation of a basal disc by the transplanted fragments on the substrate that took place within one or two months was encouraging. It is the critical phase when the fragment establishes attachment with the substrate, indicating early success of the restoration effort," says Mr. Patterson Edward, who is the director of the SDMRI.

Survival rates

Survival of the transplants is primarily based on the attachment, and it has been successful for all the monitored substrates deployed in the Gulf of Mannar, about 90% of them in the Marine National Park. The survival of the transplanted fragments during the study period between 2002 and 2024 ranged from 55.6% to 79.5% in different locations.

The highest survival rate was observed for *A. intermedia* after five years in Kariyachalli Island, with 89.1%, while the lowest was recorded for *A. valida* after five years in Poomarichan Island, with 29.3%. The highest growth rate was recorded for *A. intermedia* in Kariyachalli Island in the fifth year, with 16.7 cm a year. Generally, the genus *Acropora* showed the highest average growth rate for all sites. The slowest growth was recorded for the genus *Porites* and other massive corals, such as *Dipsastraea* and *Goniastrea*, the study shows.

The density of coral recruits was higher in TARs and PTARs than in concrete frames. The density of coral recruits in TARs was 1.23 in 2004. It increased to 24.77 in 2020. A total of 14 coral genera were found inhabiting TARs in 2020, which included *Goniastrea*, *Favites*, *Dipsastraea*, *Turbinaria*, *Pocillopora*, and *Goniopora*.

As for PTARs in Vaan Island that were deployed in 2015, the average coral recruit density was 31.49 in 2016. It increased to 76.01 in 2020. In both cases, the coral recruit density was found to increase over the years. A total of 16 coral genera were found to inhabit the surface of PTARs and eight in concrete frames.

In Vaan Island, live coral cover was 2.7% in 2006 in the restored site and it was 0% in the unrestored degraded site. Coral cover kept increasing significantly at the restored site and reached 18.8% in 2020. An increase in the live coral cover was also observed in the unrestored site, but it was very meagre as it reached only 1.8% in 2020.

The impact of coral bleaching in 2010 and 2016 was evident at the restored and unrestored sites as indicated by the decrease in live coral cover after the bleaching. However, the loss of corals at the restored sites was less than that at the unrestored sites. Coral colony density was also found to increase over time in the restored and unrestored sites of Vaan and Koswari Islands, but the magnitude of increase was much higher in the restored sites.

Fish density in the restored site of Vaan Island increased considerably during the study period from 14.5 in 2006 (250 metres) to 310.0 in 2020 and a similar trend was observed in Koswari Island. A total of 63 species in Vaan Island and 51 species in Koswari Island were recorded at the restored and unrestored sites during the study period. Coral restoration activities during the past two decades have also benefited the community dependent on the biosphere through awareness creation and capacity-building among the reef managers.

The low-cost and low-tech coral restoration activities in the Gulf of Mannar may be looked upon as a climate mitigation effort to sustain the integrity of coral reefs, associated biodiversity, and the livelihood of the dependent people, the study suggested.

'Promising results'

Supriya Sahu, Additional Chief Secretary, Department of Environment, Climate Change, and Forests, says the reef restoration efforts have shown promising results and have become integral to coral conservation strategy, and gaining international recognition. Now, the Tamil Nadu government has launched a comprehensive restoration initiative under the Tamil Nadu Sustainably Harnessing Ocean Resources (TNSHORE) programme to protect and restore the Kariyachalli Island.

"This initiative involves the deployment of 8,500 multi-purpose artificial reef modules specially designed to protect and restore the highly-eroded Kariyachalli Island, conserve and enhance biodiversity, particularly coral diversity in the context of threatening climate change implications, protect and sustain fishery resources and simultaneously restore two acres of degraded coral reefs and three acres of degraded seagrass beds," she said.

Cycle of coral restoration

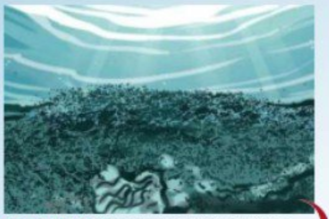

Degraded reef site: Initially, the scientists identify the degraded reef sites for direct transplantation.

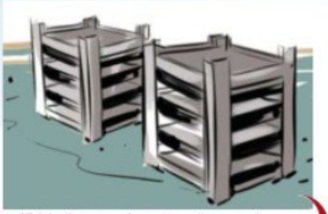

Artificial substrates: After testing with stones, clay pots and ropes, concrete frames were selected.

Deployment of substrates: Cement frames are taken to the restoration sites in rafts or small barges.

Transplantation technique: Coral fragments are tied to the frames using nylon ropes or cable ties.

ILLUSTRATION: SAAI

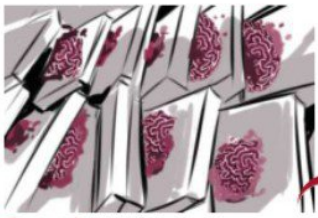

Diverse species: A total of 20 coral species were used in the transplantation at the sites.

Years of monitoring: Twenty colonies for each species were selected and fixed for monitoring.

Periodical maintenance: Maintenance works were carried out throughout the monitoring period.

Growth and survival: Over two decades, the growth, survival and biodiversity were studied.